रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2010/आषाढ़ 10, 1932
No. 179] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2010/ASADHA 10, 1932

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जून, 2010

सं. 12 (1)/2007-खान-VI.—इस मंत्रालय के दिनांक 29 जुलाई, 2003 के संकल्प संख्या 12(1)/2003-खान-VI का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से खनिज सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । खनिज सलाहकार परिषद् का गठन और उसके कार्य इस प्रकार होंगे :—

खनिज सलाहकार परिषद् का गठन

अध्यक्ष

1. खान मंत्री

सदस्य

2. सांसद (लोक सभा) श्री महेश जोशी
3. सांसद (राज्य सभा) श्री मोतीलाल वोरा
4. सचिव, खान मंत्रालय
5. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
6. महानिदेशक, खान सुरक्षा
7. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो
8. संयुक्त सचिव (पर्यावरण) पर्यावरण और वन मंत्रालय
9. महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण और वन मंत्रालय
10. इस्पात मंत्रालय (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
11. कोयला मंत्रालय (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
12. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
13. परमाणु ऊर्जा विभाग (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
14. वाणिज्य विभाग (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
15. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
16. रेल मंत्रालय (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
17. पोत परिवहन मंत्रालय (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
18. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (संयुक्त सचिव के पद सें कम न हो)
19. आर्थिक कार्य विभाग (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो—स्टाक एक्सचैंज का काम देखते हों)
20. केन्द्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
21. योजना आयोग (संयुक्त सचिव के पद से कम न हो)
22. महासचिव, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ
23. भारतीय उद्योग परिसंघ
24. एसोचेम
25. फिक्की
26. अध्यक्ष, आल इंडिया ग्रेनाइट एण्ड स्टोन एसोसिएशन
27. सचिव, खान, आंध्र प्रदेश सरकार
28. सचिव, खान, छत्तीसगढ़ सरकार
29. सचिव, खान, गोवा सरकार

30. सचिव, खान, गुजरात सरकार

31. सचिव, खान, झारखंड सरकार

32. सचिव, खान, कनार्टक सरकार

33. सचिव, खान, महाराष्ट्र सरकार

34. सचिव, खान, मध्य प्रदेश सरकार

35. सचिव, खान, उड़ीसा सरकार

36. सचिव, खान, राजस्थान सरकार

37. सचिव, खान, पश्चिम बंगाल सरकार

बारी-बारी से एकांतर वर्षों में अन्य सदस्य

38. सचिव, खान, असम सरकार अथवा सचिव, खान, मेघालय सरकार

39. सचिव, खान, हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा सचिव, खान, उत्तरांचल सरकार

40. सचिव, खान, बिहार सरकार अथवा सचिव, खान, उत्तर प्रदेश सरकार

41. सचिव, खान, हरियाणा सरकार अथवा सचिव, खान, पंजाब सरकार

42. सचिव, खान, केरल सरकार अथवा सचिव, खान, तमिलनाडु सरकार

43. अध्यक्ष, इण्डियन फेरो-अलॉय प्रोडयूसर एसोसिएशन, मुम्बई अथवा अध्यक्ष माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, हैदराबाद

44. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अथवा अध्यक्ष, गुजरात मिनरल इंडस्ट्री एसोसिएशन

45. अध्यक्ष, गोवा मिनरल और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन अथवा अध्यक्ष, ऑरगेनाइजेशन आफ माइन ओनर्स बेल्लारी होस्पेट सेक्टर

46. अध्यक्ष, ईस्टर्न जोन माइनिंग एसोसिएशन अथवा अध्यक्ष, गोवा माइनिंग एसोसिएशन

सदस्य सचिव

47. संयुक्त सचिव, खनिज नीति और कानून, खान मंत्रालय

विचारार्थ विषय

(क) भूमि और अपतट क्षेत्रों में खनिज नीति और कानून पर सलाह देना।

(ख) सतत खनन और पारिस्थितिकी संतुलन की नीतियों पर सलाह देना।

(ग) खनन क्षेत्रों में सामुदायिक और स्थानीय क्षेत्र विकास तथा खनन कार्यकलापों में स्थानीय लोगों को शामिल करने के मुद्दों पर सलाह देना।

(घ) खनिज क्षेत्र के लिए परिवहन और पीपीपी मॉडल्स और व्यवहार्यता अंतर निधियन के माध्यम से परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नीतियों सहित अवसंरचना संबंधी सहायता पर सलाह देना।

(ङ) संस्थानिक वित्त और गवेषण के लिए जोखिम कोष सहित खनन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता पर सलाह देना।

(च) तकनीकी-आर्थिक और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए खनिज क्षेत्र में घरेलू और विदेशी व्यापार और निवेश की नीतियों पर सलाह देना।

(छ) मानव संसाधन विकास संबंधी मुद्दों पर सलाह देना।

(ज) गवेषण, खनन पद्धतियों, सज्जीकरण, खनन उपकरण और नई सामग्रियों के खनन विकास, ऊर्जा बचत और अपशिष्ट को कम करने सहित खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर सलाह देना।

(झ) खनन के अग्रणी संयोजन के रूप में डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना और मूल्यबर्धन को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहनों और कराधान उपायों पर सलाह देना।

(ञ) खनन और गवेषण के लिए प्रौद्योगिकी और उपकरणों के आयात संबंधी नीतियों पर सलाह देना।

अवधि

परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष होगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता तथा परिषद् के अन्य सभी सदस्यों को भेजा जाए ।

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

RESOLUTION

New Delhi, the 30th June, 2010

No. 12(1)/2007-M-VI.—In supersession of this Ministry's Resolution No. 12/(1)2003-M-VI, dated 29th July, 2003, the Government of India have decided to reconstitute the Mineral Advisory Council with immediate effect. The composition and function of the Mineral Advisory Council as reconstituted will be as follows :

COMPOSITION OF MINERAL ADVISORY COUNCIL

CHAIRMAN

1. Minister of Mines.

MEMBERS

2. Shri Mahesh Joshi, Member of Parliament (Lok Sabha)
3. Shri Motilal Vora, Member of Parliament (Rajya Sabha)
4. Secretary, Mines

5. Director General, Geological Survey of India
6. Director General, Mines Safety
7. Controller General, Indian Bureau of Mines
8. Joint Secretary, Environment, Ministry of Environment and Forests
9. Inspector General, Forests, Ministry of Environment and Forests
10. Ministry of Steel (not below rank of Joint Secretary)
11. Ministry of Coal (not below rank of Joint Secretary)
12. Ministry of Earth Sciences (not below rank of Joint Secretary)
13. Department of Atomic Energy (not below rank of Joint Secretary)
14. Department of Commerce (not below rank of Joint Secretary)
15. Department of Industrial Policy & Promotion (not below rank of Joint Secretary)
16. Ministry of Railways (not below rank of Joint Secretary)
17. Ministry of Shipping (not below rank of Joint Secretary)
18. Ministry of Road Transport and Highways (not below rank of Joint Secretary)
19. Department of Economic Affairs (not below rank of Joint Secretary—dealing with Stock Exchanges)
20. Central Board of Excise and Customs (not below rank of Joint Secretary)
21. Planning Commission (not below rank of Joint Secretary)
22. Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries
23. Confederation of Indian Industry
24. ASSOCHAM
25. FICCI.
26. President, All India Granite and Stone Association
27. Secretary, Mines, State Government of Andhra Pradesh
28. Secretary, Mines, State Government of Chhattisgarh
29. Secretary, Mines, State Government of Goa
30. Secretary, Mines, State Government of Gujarat
31. Secretary, Mines, State Government of Jharkhand
32. Secretary, Mines, State Government of Karnataka
33. Secretary, Mines, State Government of Maharashtra
34. Secretary, Mines, State Government of Madhya Pradesh
35. Secretary, Mines, State Government of Orissa
36. Secretary, Mines, State Government of Rajasthan
37. Secretary, Mines, State Government of West Bengal

MEMBERS BY ROTATION IN ALTERNATIVE YEARS

38. Secretary, Mines, State Government of Assam or Secretary, Mines, State Government of Meghalaya
39. Secretary, Mines, State Government of Himachal Pradesh or Secretary, Mines, State Government of Uttaranchal
40. Secretary, Mines, State Government of Bihar or Secretary, Mines, State Government of Uttar Pradesh
41. Secretary, Mines, State Government of Haryana or Secretary, Mines, State Government of Punjab
42. Secretary, Mines, State Government of Kerala or Secretary, Mines, State Government of Tamil Nadu
43. President, Indian Ferro-Alloys Producers' Association, Mumbai or President Mining Engineers' Association of India, Hyderabad.
44. President, Federation of Mining Association of Rajasthan or President, Gujarat Mineral Industry Association.
45. President, Goa Mineral Ore Exporters' Association or President, Organization of Mine Owners, Bellary Hospet Sector
46. President, Eastern Zone Mining Association or President, Goa Mining Association.

MEMBER SECRETARY

47. Joint Secretary, Mineral Regulation, Ministry of Mines.

TERMS OF REFERENCE

(a) To advise on mineral policy and legislation in land and in offshore areas

(b) To advise on policies of sustainable mining and maintenance of ecological balance.

(c) To advise on issues of community and local area development in mining areas and inclusiveness of host population in mining activities.

(d) To advise on infrastructure support, including transportation for the mineral sector and policies for financing the projects through PPP models and viability gap funding.

(e) To advise on financial support for mining activities including institutional finance, and risk funds for exploration.

(f) To advise on policies for domestic and foreign trade and investments in mineral sector keeping in view techno-economic and strategic consideration.

(g) To advise on issues relating to human resource development.

(h) To advise on research and development in the mineral sector including exploration, mining methods, beneficiation, mining equipment and development of new materials, energy saving and waste reduction.

(i) To advise on taxation measures and incentives to promote value addition and setting up of downstream industries as forward linkage of mining

(j) To advise on policies on import of technology and equipments for mining and exploration.

TENURE

The tenure of the Council shall be four years from the date of notification.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the State Governments, several Ministries and Departments of the Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General-Central Revenues, Controller General, Indian Bureau of Mines, Nagpur, Director General, Geological Survey of India, Kolkata and all other members of the Council.

AJITA BAJPAI PANDEY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.